{ खुद के लिए जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता पर जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीते हैं - परमहंस योगानंद }

सम्पादकीय

सबक ले पाकिस्तान

आजकल पाकिस्तान तनाव से गुजर रहा है और इसके लिए वहां पोषित आतंकवाद की जितनी निंदा की जाए, कम होगी। एक आत्मघाती आतंकी ने विस्फोटकों से भरी कार से चीनी इंजीनियरों व श्रमिकों को ले जा रहे वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें पांच चीनी नागरिकों सहित एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान में यह तीसरा ऐसा हमला है, जब आतंकियों ने विकास कार्यों को निशाना बनाया है। अब तक नौ चीनी नागरिक आतंकी हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के शांगला जिले में हुई है, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना का काम चल रहा है। चीनी इंजीनियर दासू बांध की ओर ही जा रहे थे, जब उन पर हमला हुआ। इस हमले के बाद चीन ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया है, जिससे पाकिस्तान सरकार की चिंता बहुत बढ़ गई है। चिंता का पता इसी से चलता है कि मंत्रियों के अलावा खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीनी दूतावास जाकर अधिकारियों को आश्वस्त किया है। अमूमन राजदूतों को प्रधानमंत्री कार्यालय या विदेश मंत्रालय बुलाकर संदेश देने की परंपरा रही है, पर यह विरल मौका है, जब प्रधानमंत्री को खुद दूतावास जाना पड़ा है।

आतंकवाद दोधारी तलवार की तरह है। भारत ने बार-बार चेताया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पोसने से बाज आए, पर इतने जख्म खाकर भी वह समझने को तैयार नहीं है। आतंकवाद पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन के लिए भी व्यवसाय बढ़ाने या खुद को कूटनीतिक रूप से मजबूत करने का एक माध्यम बन गया है। अगर चीन अपने नागरिकों की निर्मम मौतों से कुछ सीखे और पाकिस्तान को आतंकियों के विरुद्ध कदम उठाने को मजबूर करे, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान सरकार वाकई इस हमले के दोषियों को पकड़ पाती है, तो इसका असर वहां आतंकवाद के नेटवर्क पर जरूर पड़ेगा। अब समय आ गया है कि इस्लामाबाद आतंकवाद को लेकर गंभीर हो जाए, क्योंकि अगर फिर से चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, तो पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजिंग आज हर तरह से इस्लामाबाद का मददगार बना हुआ है, इसके बावजूद पाकिस्तानी धरती पर सक्रिय आतंकवादी यदि चीन के नागरिकों को ही निशाना बनाते हैं, तो यह पाकिस्तानी सत्ता-प्रतिष्ठान के लिए वाकई चिंता की बात होनी चाहिए। पाकिस्तानी तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपने हमले इधर बढ़ा दिए हैं। पिछले सप्ताह ही, ग्वादर बंदरगाह के बाहर चीनी नागरिकों को ले जा रहे एक काफिले पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आठ आतंकियों को मार डाला था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से आजादी चाहती है। पाकिस्तान आजादी की इस पुरानी मांग को खारिज करता रहा है, पर उसे आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी से लड़ना चाहिए। भारत के साथ फिजूल दुश्मनी में पाकिस्तान ने काफी कुछ गंवाया है और अब जब वह आर्थिक रूप से बदहाल हो चुका है, तब उसके लिए विकास पर पूरी तरह से ध्यान देने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर वह विकास की ओर ध्यान नहीं देगा, और उधार, अनुदान में फंसता चला जाएगा, तो उसके प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ही दूतावासों में जाकर सफाई देने की दुखद नौबत आती रहेगी।

वि शे ष

सियासी मैदान में महिलाओं की मजबूती

आम चुनाव का आगाज हुआ और महिलाओं के खिलाफ बदजुबानी तेज होती दिख रही है। दो-ढाई दशक पहले तक महिलाओं के खिलाफ ऐसे 'सेक्सिस्ट रिमार्क', यानी अशोभनीय टिप्पणियां नजरंदाज कर दी जाती थीं, लेकिन अब महिलाएं खुद इसके खिलाफ मुखर होने लगी हैं। सोशल मीडिया का भी साथ उनको मिलता है। इस लिहाज से देखें, तो यह महिलाओं में बढ़ती जागरूकता का संकेत है कि अब वे अपने खिलाफ किसी अभद्र शब्दावली को चुपचाप स्वीकार नहीं करतीं और बयानवीरों को या तो माफी मांगनी पड़ती है या अपने बयान को नकारना पड़ता है।

■ नीरजा चौधरी

आम चुनाव का आगाज हुआ और महिलाओं के खिलाफ बदजुबानी तेज होती दिख रही है। दो-ढाई दशक पहले तक महिलाओं के खिलाफ ऐसे 'सेक्सिस्ट रिमार्क', यानी अशोभनीय टिप्पणियां नजरंदाज कर दी जाती थीं, लेकिन अब महिलाएं खुद इसके खिलाफ मुखर होने लगी हैं। सोशल मीडिया का भी साथ उनको मिलता है। इस लिहाज से देखें, तो यह महिलाओं में बढ़ती जागरूकता का संकेत है कि अब वे अपने खिलाफ किसी अभद्र शब्दावली को चुपचाप स्वीकार नहीं करतीं और बयानवीरों को या तो माफी मांगनी पड़ती है या अपने बयान को नकारना पड़ता है। कंगना रनौत प्रकरण इसका ज्वलंत उदाहरण है।

हालांकि, राजनीति ही एकमात्र ऐसी जगह है, जहां महिलाओं को पर्याप्त अहमियत नहीं मिल रही। संसद और विधानसभाओं में उनकी निराशाजनक हिस्सेदारी इसकी तस्दीक करती है। हम 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन संसद में महिलाओं की मौजूदगी 15 फीसदी भी नहीं है। यह स्थिति तब है, जब महिलाओं ने हरेक क्षेत्र में तमाम बाधाओं को पार पाते हुए अपना मुकाम बनाया है। बेशक, 1993 में पारित संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा क्रमश: पंचायतों व नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसके कारण जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव आया है, लेकिन प्रधान-पति या पंच-पति जैसी संकल्पना आज भी कायम है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक गांव में पिछले हफ्ते एक ऐसे ही प्रधान-पति के साथ मेरा वास्ता पड़ा। हालांकि, कई अध्ययन यही बताते हैं कि सामाजिक सुधार की दिशा में महिलाएं पुरुष प्रतिनिधि की तुलना में कहीं बेहतर काम करती हैं।

जाहिर है, राजनीति में एक तरफ महिलाएं खुद को स्थापित कर रही हैं, तो दूसरी तरफ उनका इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। नामचीन चेहरों पर ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी दांव लगाना पसंद करती हैं। स्थानीय निकायों में भले ही महिला जन-प्रतिनिधियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है, मगर सियासी पार्टियों की नजर में उनका मानो महत्व ही नहीं। आरोप लगाए जाते हैं कि महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में संसाधनों का अभाव होता है और वे जीत की गारंटी भी नहीं होतीं।

यही कारण है कि संसद से पारित 33 फीसदी महिला आरक्षण के जमीन पर उतरने की उम्मीदें अभी कम नजर आती हैं। यदि राजनीतिक दलों की मंशा सही होती, तो इसमें परिसीमन का पेच नहीं जोड़ा जाता। कहा जा रहा है, परिसीमन के बाद दक्षिण में लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी, जबकि उत्तर भारत में बढ़ जाएंगी, क्योंकि यह कवायद जनसंख्या पर आधारित है और दक्षिण के सूबे अपने बेहतर शासन से जनसंख्या वृद्धि को थामने में सफल रहे हैं। वहां परिसीमन को 'दंड' के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु की विधानसभा ने तो इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास कर दिया है। स्पष्ट है, अगर परिसीमन का मसला कानूनी दांव-पेच में फंसा, तो 2034 तक भी महिला आरक्षण सच्चाई नहीं बन सकेगा। अगर सियासी दलों की नीयत ठीक होती, तो वे ऐसे प्रावधान के बिना भी महिला प्रत्याशियों पर भरोसा कर सकते हैं। मगर किसी दल ने अब तक ऐसी सदिच्छा नहीं दिखाई है। आज महिला जन-प्रतिनिधियों को कई मोर्चों पर जूझना पड़ता है। पारिवारिक विरासत के तहत राजनीति में उतरने वाली महिलाओं को यदि दरकिनार कर दें, तो आम महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की राजनीति तक पहुंचना टेढ़ी खीर से कम नहीं है। सबसे पहले उन्हें राजनीति में आने के लिए अपने परिवार को मनाना पड़ता है, फिर स्थानीय स्तर पर पार्टी को इस बाबत संतुष्ट करना पड़ता है कि चुनाव में उन पर भी भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद उनका नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास जाता है, जहां की अपनी चुनौतियां होती हैं। यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चर्चा लाजिमी है। बेशक, उनकी सियासत की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी 'गॉडफादर' के उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है कि आज भाजपा को प.बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपना पूरा दम-खम लगाना पड़ रहा है।

आम चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र की बारामती सीट भी काफी अहम है। यहां एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच जंग तय मानी जा रही है। यह पवार परिवार की पारंपरिक सीट है, लेकिन इस बार मुकाबला परिवार के भीतर ही है। एक तरफ शरद पवार की बेटी हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बहू। इसका अर्थ है कि यहां की जीत से एनसीपी का भविष्य भी तय होगा। इससे यह भी पता चलेगा कि क्या वहां की राजनीति में शरद पवार अब भी अहम हैं या अजित पवार महाराष्ट्र के उभरते सितारे हैं? वैसे, भाजपा की तरफ से बांसुरी स्वराज को टिकट मिलने से नई दिल्ली सीट पर भी नजर बनी रहेगी। विधानसभा के लिहाज से यह सीट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। ऐसे में, बांसुरी यदि यहां से जीतती हैं, तो अपनी मां सुषमा स्वराज की परंपरा को आगे बढ़ाएंगी और उनको भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

संकेत साफ है, महिलाओं में बढ़ते राजनीतिक रुझान को देखते हुए सियासी दलों के लिए ज्यादा दिनों तक उनको नजरंदाज करना मुश्किल है। वैसे भी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगले एक दशक में किसी निर्वाचन क्षेत्र में करीब 55 फीसदी महिलाएं मत डालेंगी, जबकि 45 फीसदी पुरुष, तो उम्मीद यही है कि आने वाले चुनावों में महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ेगी। महिलाएं किस तरह किसी दल की जीत का आधार बनती हैं, इसका अंदाजा हरियाणा और आंध्र प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मुखर महिलाओं को देखकर ही हो गया था। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के समय तो मजाक में यह भी कहा जाता था कि मंदिर आंदोलन की खिलाफ मुखर मुलायम सिंह के परिवार की महिलाओं ने भी भाजपा को वोट दिया है। बिहार में नीतीश कुमार की जीत भी महिलाओं में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी महिला मतदाताओं का खासा रुझान है। इसीलिए सभी दल बतौर वोट-बैंक महिलाओं को लुभाने लगे हैं। अब जरूरत इस ऊर्जा को नेतृत्व की भूमिका सौंपने की है। इससे हमारा लोकतंत्र क्रांतिकारी बदलाव का गवाह बनेगा।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

प्रदेश

बच्चे-बुजुर्गों के साथ समय बिताएं : एस. पारेख

पद्म भूषण अवॉर्डी दीपक एस पारेख जेकेएलयू लॉरिएट अवॉर्ड से सम्मानित

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। बुजुर्ग और युवा दोनों के साथ समय बिताइए, आपको निश्चित तौर पर नए आइडिया मिलेंगे, अलग अलग दृष्टिकोण के लोग हमे नया सिखाते है। कुछ ऐसे ही प्रेरक उद्बोधन के साथ पद्म भूषण से सम्मानित एचडीएफसी के पूर्व चेयरपर्सन दीपक एस पारेख बुधवार को जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी में देशभर से आए स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक एवम बिजनेस पर्सन्स से रू-ब-रू हुए। उन्हे यूनिवर्सिटी की ओर से प्रतिष्ठित जेकेएलयू लॉरिएट अवॉर्ड से नवाजा गया। जेके समूह के संस्थापक हरि शंकर सिंघानियां की स्मृति में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर योगदान के लिए ख्यातनाम हस्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जेकेएलयू लॉरिएट अवॉर्ड का यह नौवा एडिशन था, इस अवॉर्ड से पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. प्रणव मुखर्जी समेत अन्य नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी

के प्रो चांसलर आरपी सिंघानिया एवम एचपी सिंघानिया के साथ जेकेएलयू के वाइस चांसलर प्रो. धीरज सांघी ने यह पुरस्कार प्रदान किया। पारेख ने संबोधित करते हुए कहा कि फाइनेंशियल ग्रोथ एथिकल होनी चाहिए, हमे वित्तीय लालच और अहंकार से होने वाले खतरे से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। यही स्थाई सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। एथिक्स को दाव पर लगाकर की गई ग्रोथ के कोई मायने नहीं होते है।

युवाओं के लिए अवसरों की भरमार : 'विकसित भारत/विजन इंडिया 2047, युवाओं के लिए अवसर' विषय पर संबोधित करते पारेख ने कहा कि भारत में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं है, उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो जाएगा। वही अनुमान है कि 2030 तक देश के विकास के साथ ही स्टॉक मार्केट 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। उन्होंने 2047 तक देश के विकसित होने का विजन रखते हुए युवाओं के लिए इसमें अपार संभावनाएं बताई। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन एवम स्कारात्मक सोच के साथ युवा काफी आगे बढ़ सकते है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को 10 लाख दावा राशि अदा करने के निर्देश

मॉर्निंग न्यूज @ जोधपुर। स्थाई लोक अदालत ने अधिस्वीकृत पत्रकार की ओर से जमा बीमा प्रीमियम को लौटाए बिना ही मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी रद्द करने को त्रुटिपूर्ण, अनुचित और अविवेकपूर्ण निर्णय घोषित करते हुए सूचना एवमं जनसंपर्क निदेशालय तथा सूचना जनसंपर्क अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रार्थी को 10 लाख रुपए दावा राशि अदा करें।

प्रकरण मंजूर करते हुए अदालत के अध्यक्ष सुकेश कुमार जैन और सदस्य जेठमल पुरोहित तथा माणकलाल चांडक ने पांच हजार रुपए व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। पत्रकार गौतम चंद जैन ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से जन उपयोगी सेवा के तहत प्रकरण पेश कर कहा कि राजस्थान सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकार चिकित्सा सुविधा योजना 2009 प्रारंभ करते हुए 10 लाख रुपए की मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी जारी की और 20 अक्टूबर 2017 से एक साल के नवीकरण वास्ते प्रार्थी ने चार हजार रुपए प्रीमियम अदा किया तथा सूचना एवम जन संपर्क निदेशालय ने अपने हिस्से का भी प्रीमियम मिलाकर राज्य बीमा एवम प्रावधाई निधि विभाग को प्रेषित कर दिया।

प्रार्थी के कैंसर ग्रसित होने पर एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट,मुंबई में इलाज के 13 लाख रुपए से अधिक का खर्च होने पर विपक्षी के यहां दावा पेश किए जाने पर स्टेट इंश्योरेंस ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि उन्होंने वर्ष 2017 18 का बीमा नवीकरण नहीं किया है सो वे दावे के वास्ते दाई नहीं है। अधिवक्ता भंडारी ने बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी ने जब एक बार अपने हिस्से का बीमा प्रीमियम सूचना एवम जन संपर्क निदेशालय को अदा कर दिया और उन्होंने स्टेट इंश्योरेंस को अपने हिस्से का प्रीमियम मिलाकर प्रेषित कर दिया और प्रार्थी को किसी भी विपक्षी ने न तो यह सूचित किया कि बीमा पॉलिसी नवीकरण नहीं किया गया है या रद्द कर दी गई है।

ताज सिर्फ सिर की सजावट नहीं, महिलाओं के आत्मविश्वास का प्रतीक है : मदान

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। मिसेज इण्डिया यूनिवर्स आर्गेनाइजेशन दीवालिशियस ग्रुप की ओर से 31 मार्च 2024 को जेएलएन मार्ग स्थित होटल ग्रैंड उनियारा में इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट 'दीवालिशियस मिसेज इण्डिया यूनिवर्स-2024' की विजेता प्रतिभागियों की क्राउनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में देश भर की ख्यातनाम सुंदरियों के बीच कड़े मुकाबले में टॉप पर पहुंची 10 पार्टिसिपेंट्स के सिर पर नामी गिरामी हस्तियों के हाथों ताज पहनाकर उन्हें विभिन्न टाइटल्स से नवाजा जाएगा। इस दौरान दीवालिशियस मिसेज यूनिवर्स आर्गेनाइजेशन की ओर से लॉन्च की जाने वाली पांच अंतरराष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिताओं की घोषणा भी की जाएगी। दीवालिशियस मिसेज इण्डिया यूनिवर्स आर्गेनाइजेशन के सीईओ नरेश मदान और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर डॉ. आशीष गौड़ ने बताया कि इस बार मिसेज इण्डिया यूनिवर्स के लिए

प्रतिभागियों की भीड़ न जुटाकर चुनिंदा प्रतिभागियों का ही ऑनलाइन प्रोसेस से चयन किया गया है, जिनकी 2 दिन तक ग्रूमिंग के बाद सभी फाइनलिस्ट को 31 मार्च 2024 को होटल ग्रैंड उनियारा में होने वाली क्राउनिंग सेरेमनी में ताज पहनाने के साथ ही विभिन्न टाइटल्स से सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं को पहनाया जाने वाला ताज सिर्फ सिर की सजावट मात्र ही नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास का प्रतीक भी है।

फेडरेशन कप के लिए राजस्थान बॉडी बिल्डिंग टीम का चयन

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। गोवा में 6 अप्रैल से आयोजित होने वाली फेडरेशन कब बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिकल फिटनेस के लिए राजस्थान टीम का चयन रोबस्ट जिम जयपुर पर किया गया राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि 80 किलोग्राम वर्ग में ऐश्वर्या, 85 किलोग्राम में अमित जांगिड़, 95 किलोग्राम में नीरज कुमार तथा मेंस फिजिक में इंदर कुमार टॉक का सेलेक्शन किया गया। टीम के मैनेजर राजेश यादव कोषाध्यक्ष राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन व कोच सनी जैन होंगे।

सड़क दुर्घटना में अज्ञात मृतक के वारिसान की तलाश

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। 23 मार्च को समय शाम 6.00 बजे के लगभग श्री श्याम टिम्बर एण्ड प्लाई बुड के सामने एक्सप्रेस हाईवे रोड पर 200 फिट से 14 नम्बर की तरफ जाने वाली रोड पर सड़क दुर्घटना में अज्ञात व्यक्ति चोटग्रस्त होने पर मृत अवस्था में पुलिस को पड़ा हुआ मिला है। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मृतक की डेड बॉडी कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर के डीप फ्रीज में रखवाई है। सड़क दुर्घटना अनुसंधान ईकाई (पश्चिम) यातायात की ओर से अज्ञात मृतक का हुलिया जारी करते हुए बताया है कि मृतक की उम्र करीब 45 वर्ष, रंग सांवला, कद 5 फिट 3 इंच, सर पर काले बाल, दाढ़ी बढ़ी हुई, सफेद बाल व हल्की मूंछे है। मृतक के सबंध में किसी भी प्रकार की सूचना सड़क दुर्घटना अनुसंधान ईकाई (पश्चिम) यातायात को दूरभाष नम्बर 0141-2209040 या 97840763 पर दी जा सकती है।

शहर के बाहर बस रहीं अवैध कॉलोनियां, प्रशासन रोकने में नाकाम

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। शहर के बाहरी इलाकों में अवैध कॉलोनियां बस रही हैं। इनको रोकने के लिए प्रवर्तन शाखा के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब प्रवर्तन शाखा के पास अच्छा खासा स्टाफ है। इसके बावजूद कई ऐसी अवैध कॉलोनियां फिर से बसना शुरू हो गई, जिन पर पिछले छह माह में कार्रवाई हो चुकी है। जयसिंहपुरा खोर, कालवाड़ रोड और आगरा रोड पर ऐसा ही हाल है। कृषि भूमि का भू-रूपांतरण कराए बगैर कॉलोनी सृजित की जा रही है। लोगों को जेडीए अप्रूव्ड कराने के सपने दिखाकर कृषि भूमि का बेचान किया जा रहा है।